



# Polity

## Explanation (TEST : 03)

10 July, 2018 (06:30 pm)

1. (d) कथन 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, अतः अभीष्ट उत्तर (d) होगा।
2. (c) विकल्प (c) सही सुमेलित है।  
◦ उत्प्रेषण : न्यायिक एवं अर्द्ध-न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है।
3. (c) अनुच्छेद-35 : इसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है।
4. (c) कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, अतः अभीष्ट उत्तर (c) होगा।
5. (d) कथन 1 असत्य है : राज्य के लिए समान सिविल संहिता बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, राज्य को नहीं।  
कथन 2 असत्य है : समान सिविल संहिता से संबंधित प्रावधान, संविधान के भाग चार (नीति निर्देशक तत्व) में उल्लिखित है।
6. (a) राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में विकल्प 1, 2 और 3 शामिल है।  
◦ विकल्प 1 : समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता।  
◦ विकल्प 2 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।  
◦ विकल्प 3 : कृषि एवं पशुपालन का संगठन।  
अतः अभीष्ट उत्तर (a) होगा।
7. (b) निःशुल्क विधिक सहायता 39(क) नीति निर्देशक तत्वों में बाद में जोड़ा गया है। अतः अभीष्ट उत्तर (b) होगा।
8. (b) किसी समूह को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान करने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। अतः कथन 1 असत्य है। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। अतः कथन 2 सत्य है। अतः अभीष्ट उत्तर (b) होगा।
9. (b) भारत के संविधान में 'कल्याणकारी राज्य' का आदर्श 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' में निहित है। अतः अभीष्ट उत्तर (b) होगा।
10. (a) सही सुमेलित है-  
(a) अनुच्छेद-45 : 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था में देखरेख तथा शिक्षा का प्रबंध करना।  
(b) अनुच्छेद-40 : पंचायतों में देखरेख तथा शिक्षा का प्रबंध करना।  
(c) अनुच्छेद-39(a) : स्त्री व पुरुष दोनों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करना।  
(d) अनुच्छेद-39(A) : समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता।

### ANSWER KEY

### Polity (10 July, 2018) Test No. 03

1.	(d)	2.	(c)	3.	(c)	4.	(c)	5.	(d)	6.	(a)	7.	(b)	8.	(b)	9.	(b)	10.	(a)
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----